वीरेन्द्र सिंह बड़ी अच्छी ड्रेस में आये हैं- उन्होंने पगड़ी पहनी है। आप उन्हें आदेश दें कि वह रोज पगड़ी पहन कर आया करें।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके लिए भी कल पगड़ी मंगवा देंगे।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Thank you, Sir.

I want to tell the Minister that the forests are being destroyed not oniy in Rajasthan, but throughout the country, including Andhra Pradesh. Is the Minister going to put a ban on the cutting of trees at least for 50 years, particularly in Rajasthan ? Already, the whole of Rajasthan has become a desert. There is a possibility that the whole of India will become a desert, if the forests are cut.

Regarding fuel, I want the Minister to recommend to the Minister of Energy to sanction more gas agencies to that area, so that they may use gas, instead of fuel. Is he going to put a complete ban ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is difficult to put a ban for 50 years in any particular State; but as I have already told the Members, this Forests Conservation Act, 1980 has been enacted only for this purpose.

**अध्यक्ष महोदय** : जब श्री राम गोपाल रेड्डी साफा बांध लेंगे, तो ऐसे सवाल नहीं करेंगे।

**श्री भोखाभाई** : अध्यक्ष महोदय, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों का राजस्थान सरकार के वन अधिकारियों के साथ वांछित सहयोग नही है। यह सही है कि राजस्थान में कंट्रेक्टर सिस्टम बन्द हो गया है, लेकिन वहां पर एक और व्यवस्था शुरू हुई है, जिसका नाम है डिपार्टमेंटल वर्किन्ग। वह काम में उतनी गड़बड़ करता है, जितनी कि कंट्रेक्टर करते हैं। क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी ? खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी और सिरोही जिलों में वन हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी लकड़ी बेचने के लिए फारेस्ट काटते हैं, तो वे उसमें गड़बड़-घोटाला करते हैं। जो फ्युल की लकड़ी और इमारती लकड़ी काटी जाती है, वह बाजार भाव से बड़ी मंहगी बेची जाती है। क्या मंत्री महोदय इस गड़बड़ पर रोक लगाएंगे ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने पहले ही बताया है कि एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अच्छा सहयोग है। माननीय सदस्य ने डिपार्टमैंटल वर्किन्ग की बात कही है। फारेस्ट मे पेड़ो को काटने के लिए एक वर्किन्ग प्लान बनाया जाता है। इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्ज फार प्रेपेरेशन आफ वर्किन्ग प्लान्ज फार फेलिंग इन फारेस्ट्स दी गई है। उकनो बताया गया है कि पेड़ों को इस ढंग से न काटा जाए कि फारेस्ट को नुकसान हो। रीजेनीरेशन के लिए तीस, चालीस, पचास साल के बाद पेड़ों को काटा जाता है और रीप्लान्टेशन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से हर स्टेट गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में गाइडलाइन्ज दी गई हैं।

## जनजाति उपयोजनाओं के लिए सिंचाई परियोजनाएं

*949. **श्री मनोहर लाल सैनी** :

**श्री भीम सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए 174 बृहद और

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में यह परियोजनाएं कब से चल रही है;

(ग) उन परियोजनाओं के पूरी होने का निर्धारित समय क्या है;

(घ) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समयानुसार पूरी हो गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) During the VI Five Year Plan, 178 major and medium irrigation projects have been under various stages of construction in the tribal sub-plan. Out of this, 145 projects were continuing schemes and the remaining 33 new projects have been taken up during the VI Plan period.

(c) Out of 178 projects, 17 projects have since been completed and 56 more are likely to be completed by the end of VI Plan. The remaining projects will spill-over to the VII Plan. Since the VII Plan is not yet finalised it will not be possible to indicate the scheduled date of completion as this will depend upon availability of resources with the States.

(d) and (e) It is a general experience that the States have not been able to provide adequate financial resources for completing the projects as per schedule. It is also seen that for a variety of reasons the costs of the project escalates. This also comes in way of completion of the projects as per schedule. At times States take up a large number of projects, thus spreading their resources thinly. Mainly on account of the above reasons it has not been possible for the States to complete the projects as scheduled.

**श्री मनोहर लाल सैनी** : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ट्राइबल सब-प्लान एरिया में जो सिंचाई योजनायें हैं, उनके बारे में था जिसका जवाब मंत्री जी ने जो दिया है वह अधूरा और असंतोषजनक है। मैंने सवाल पूछा था कि ये बड़ी योजनायें कब से चल रही हैं तो मन्त्री जी को इस बारे में निश्चित रूप से बताना चाहिए था लेकिन उन्होंने कह दिया कि पहले से चल रही हैं। शायद मेरे इस सवाल को पूछने के पहले से तो चल ही रही हैं लेकिन मैं तो निश्चित तारीख जानना चाहता था कि कब से चल रही हैं और कितने एकड़ जमीन की सिंचाई करने की योजना बनाई गई है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : श्रीमन्, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि छठी योजना के अन्तर्गत कितने काम प्रारम्भ किए गए, कितने पहले से चले आ रहे थे, कितने कार्य इस योजना में समाप्त होंगे और कितनी योजनायें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जायेंगी।

**श्री मनोहर लाल सैनी** : मैंने तो पूछा था कि कब से, किस तारीख से ये योजनायें चलाई जा रही हैं लेकिन आपने कह दिया कि वर्षों से चल रही हैं।

**श्री राम निवास मिर्धा** : मैंने बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के पहले से कितनी चल रही हैं; छठी योजना के अन्तर्गत कितनी ली गई और कितनी इस योजना में समाप्त हो जायेंगी—यह सारे आंकड़े दिए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : तारीख लिखवाकर आपके पास भेजवा दूंगा—बस ठीक है।

**श्री राम निवास मिर्धा** : यदि 178 योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि किस तारीख चली तो वह भी मैं दे सकूंगा लेकिन

किसी विशेष योजना में दिलचस्पी हो तो वह मैं अभी बता दूं।

**श्री मनोहर लाल सैनी** : जो जानकारी मैंने चाही है वह तो आप सभा पटल पर रखेंगे और भेजवायेंगे लेकिन इसके साथ ही यह भी बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में जिन 33 नये प्रोजेक्ट्स का आपने हवाला दिया है उनकी क्या कास्ट है ? आपने अपने जबाव में यह भी कहा है कि स्टैट्स के पास रिसोर्सज नहीं होते और इसलिए योजनायें लटकती है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन 33 योजनाओं की क्या कास्ट है और जब तक ये योजनायें पूरी होंगी तव तक इनकी क्या कास्ट हो जायेगी ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : 178 योजनाओं की अनुमानित लागत 4045 करोड़ है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन योजनाओं पर कुल अनुमानित लागत 1316 करोड़ होने की संभावना है। यह कब समाप्त होंगी इस सम्बन्ध में मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना बन रही है इसलिए अभी कोई संकेत हम नहीं दे सकते कि कितनी राशि किस मद में मिलेगी, विभिन्न राज्यों को कितना पैसा सिंचाई के लिए मिलेगा। अभी यह कहना भी सम्भव नहीं है कि यह योजनायें समाप्त कब होंगी।

**श्री भीम सिंह** : मंत्री जी ने जो जबाव दिया उसमें मंजूर किया कि 145 योजनायें पहले से निर्माणाधीन थी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल से और इस प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना में आकर 15 वर्ष में 17 योजनायें कंप्लीट हुई जिसका अर्थ यह है कि लगभग एक वर्ष में एक योजना कंप्लीट हुई है। अब 105 योजनायें अगली योजना में कैरी फार्वर्ड होंगी तो क्या हम यह मानकर चलें कि यह योजनायें 105 वर्षों में पूरी हों पायेंगी ? उत्तर से जो नतीजा निकल रहा है, क्या इससे आप सन्तुष्ट हैं ? क्या ये सब योजनायें 105 वर्षों में खत्म होंगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : आशा ही जीवन है।

**श्री राम निवास मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर में बतला चुका हूं कि ये योजनायें इतना समय क्यों लेती हैं। एक कारण तो मैंने यह बतलाया है कि राज्य सरकारें···

**श्री भीम सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये 105 वर्ष में पूरी होंगी ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : आप को मेरा उत्तर सुनना चाहिये। राज्य सरकारें सातवीं योजना में कितनी प्राथमिकता सिंचाई के लिए अपनी योजनाओं में देती हैं—यह उस पर निर्भर करेगा। जो भी योजनायें आज चल रही हैं उन को समाप्त करने में वे चाहे जितने वर्ष लगा लें—पता नहीं किस हिसाब से अपने 105वर्ष कहा है—लेकिन यह सही है कि इन योजनाओं के समाप्त होने में बहुत समय लग रहा है। उस का कारण यह है कि अपने सीमित साधनों को दृष्टि में न रखते हुए भिन्न-भिन्न वजूहात से उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में योजनाओं को लिया है। लेकिन फिर भी राज्य सरकारों के सम्बंध में इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा—जहां तक 80 फीसदी पैसा जो राज्य सरकारों को दिया जाता है, वे योजना आयोग और हमारे सहयोग से जो सलाह देते हैं, चालू योजनाओं पर खर्च करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा योजनायें चालू हो चुकी हैं और हम और आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र में नई योजनायें शुरू हों, ऐसी स्थिति में योजनायें चालू हो जाती हैं और पुरानी योजनायें लम्बे समय तक चलती रहती हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : मंत्री महोदय ने जो लम्बा चौड़ा जवाब दिया है वह संक्षेप में टकराने वाला जवाब कहा जा सकता है। I think that his offiicers have drafted the answer on what I would like to caII the, 'Yes; Minister, formula', उसमें आंकड़े भर दिये हैं—5वें, छठे और सातवें प्लान के,

In the end you get confused and you do not know what you wanted to ask. But I would like to ask the Minister a simple question. He mentioned in the reply,"...The States have not been able to provide adequate financial resources for completing the projects", and again, he says," States take up a large number of projects, thus spreading their resources thinly. Mainly on account of the above reasons..." and so on. I would like to ask the hon. Minister whether it is not a fact that there are many State Governments where lakhs and lakhs of rupees lapse as the end of the year in their respective States. If this is a fact, then, what is the Minister going to do about it to monitor them and to take action against such States. It is the failure of the State Governments. It is not a question of the inadequacy of funds. I would like to know what the Minister is thinking of doing about it.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Before he answers the question I would like to know one thing There is an allegation. He said that the answers are written by the officers. Do you agree to it ? And, what is the reply of the Minister ?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : I said, 'drafted'.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Who prepares the answers ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I take full responsibility for everything that I say in the House. You need not go behind that. I stand by every word that I say here. And, I will also justify whatever I say. There is no use asking us who prepares this and that. We all take full responsibility for what we say. Everyone in the Ministry, from the highest to the lowest is responsible.

As regards the question of funds lapsing, our experience on the other hand is that the States go on making repeated demands for more and more funds. So, if in some States, a few lakhs of rupees lapse, that is a different matter. But by and large most of the funds that are required for irrigation are provided to the State Governments they spend everything we give and over and above we receive complaints, or requests for augmenting of those funds.

श्री दलीप सिंह भूरिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा—ट्राइबल एरियाज में इरिगेशन की योजनायें बनाने के लिए क्या मापदण्ड है ? आज जो इतनी सारी योजनायें पेण्डिग हैं उनका एक कारण यह भी है कि ट्राइबल एरियाज में जो पैसा इन योजनाओं पर यूटिलाइज होना चाहिए, वह दूसरी जगह खर्च कर दिया जाता है, इस लिए हमारी योजनायें पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा इस तरह से डाएवर्ट कर दिया जाता है उसका मापदण्ड क्या है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र के लिए उपयोजना बनाने का मकसद यही है कि जो साधन राज्य सरकारों के पास या केन्द्र सरकार के पास निर्धारित किए गए हैं, उनका ठीक तरह से उपयोग होता है या नहीं। इस उपयोजना का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जा सकें। उसकी मोनिटरिंग हर मिनिस्ट्री अपने-अपने क्षेत्र में करती है। भारत सरकार गृह मंत्रालय बिशेष रूप से इसके लिए मोनिटरिंग करता है। समय-समय पर मीटिंग भी बुलाई जाती हैं। इसलिए यह कहना उचित

नहीं होगा कि उनको प्रापर तरीके से मोनिटर नहीं किया जाता है। मोनिटर अवश्व किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य बतला रहे हैं कि ट्राइबल सब-प्लान का पैसा किसी और कार्य में डाइवर्ट कर दिया गया है, ऐसी जानकारी हमारे पास कोई नहीं है। यदि उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो वे हमें बता दें, हम उसको जरूर देखेंगे।

खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि

*950. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरों द्वारा तेलों की जमाखोरी के कारण विभिन्न किस्मों के खाद्य तेल के मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या जनवरी-फरवरी, 1984 के दौरान समूचे देश में तेल व्यापारियों के गोदामों पर छापे मारे गये थे तथा अवैध रूप से जमा रखे खाद्य तेलों के लाखों टिन जब्त किये गये थे;

(ग) क्या यह जमाखोरी स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से की जा रही है और यदि नहीं, तो रांची में 4 फरवरी को 6 बड़े व्यापारियों से जब्त किये गये हजारों टिनों को वापस करने तथा झरिया के व्यापारियों को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर देने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कुल मिलाकर विजिन्न किस्मों के जब्त किए गए खाद्य तेल का ब्यौरा क्या है तथा क्या यह तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा गया अथवा उनके मालिकों को वापस लौटा दिया गया ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) There has been some increase in the prices of edible oils except mustard oil the price of which has declined. The inceease in prices is due to several factors including the continuing impact of the drought of 1982 and increased demand. As per information received from the States and Union Territories, the increase in the prices of edible oils is not generally attributed to hoarding.

(b) The State Governments of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Chandigarh have reported to have conducted raids on the godowns of oil merchants in January-February, 1984 in which 12,12,720 kgs plus 27, 627 tins of different kinds of edible oils had been seized.

(c) The State Government of Bihar has reported that no hoarding is made with the connivance of officers. Out of 14,090 tins of different kinds of edible oils seized from six traders in Ranchi District, 7,129 tins have been released under orders of the Ranchi Bench of the High Court of Patna. For the remaining 6,961 tins, securities have been asked for from the traders by the Government of Bihar before release as directed by the Ranchi Bench of the High Court of Patna. There was not any case of release of traders after arrest in Jharia as per report received from the Government of Bihar.

(d) Edible Oils seized during January-February, 1984 as reported by State Governments/Union Territories